

Crude oil steadies after rallying on US stock dip



London: Crude oil prices steadied above \$88 a barrel after rallying in the previous session on a surprise fall in US crude stocks and a drop in business activity in the world's largest oil consumer. Brent crude futures fell 24 cents to \$88.18 a barrel by 1024 GMT. US West Texas Intermediate crude futures lost 33 cents to \$83.03 a barrel. REUTERS

Govt okays use of B-heavy molasses stock at sugar mills for ethanol output

Prabhudatta Mishra

New Delhi

The government has allowed the use of the B-heavy molasses (BHM) lying with sugar mills to make ethanol, which may see oil marketing companies (OMCs) reallocating ethanol quota to distilleries in the next 2-3 days.

The move will not affect sugar availability as fresh B-heavy molasses will not be used for ethanol production, official sources said.

“Only the BHM stock already with sugar mills until March 31 is to be converted,” an official source said.

The government hopes to generate an additional 60 crore litres of ethanol to help meet the targeted 15 per cent ethanol blending



Sugar availability intact with use of existing, instead of fresh B-heavy molasses for ethanol production, officials say

with petrol for the 2023-24 ethanol supply year (November-October), against 12 per cent achieved so far.

Industry data show that OMCs have targeted pur-

chase of 235 crore litres of ethanol from sugar-based distilleries and 166 crore litres from grain-based plants.

Nearly 130 crore litres of ethanol have been supplied by sugar-based distilleries and 100 crore litres by grain-based plants.

According to the fortnightly production update from the Indian Sugar & Bio-energy Manufacturers Association (ISMA) on April 16, domestic sugar output touched 310.93 lakh tonnes (lt) until April 15, from October 1, 2023, as against 312.38 lt in the year-ago period.

This excludes the quantity diverted to ethanol production.

ISMA is hopeful of achieving 320 lt sugar production this year (excluding diversion to ethanol), according to its director general, Deepak Ballani.

QUICKLY.

IGX launches small-scale natural gas contracts



New Delhi: Indian Gas Exchange (IGX) said that it has launched contracts of small-scale liquefied natural gas (ssLNG) on its platform after it received approval from the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. This move marks a significant step towards addressing the demand of natural gas in areas that are not connected to the national gas grid, the platform said. OUR BUREAU



IGX launches ssLNG contracts

Close on the heels of receiving approval from the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB), the Indian Gas Exchange (IGX) has launched contracts for small-scale Liquefied Natural Gas (ssLNG) on its platform in a bid to address the demand for fuel in areas not connected to the national gas grid. "The introduction of ssLNG contracts on IGX aims to address the growing gas demand from industries and CGD (City Gas Distribution) companies that do not have access to pipeline networks," IGX said in a statement.

IGX launches ssLNG contracts, to take gas availability beyond national grid

PTI ■ NEW DELHI

Close on the heels of receiving approval from the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB), the Indian Gas Exchange (IGX) has launched contracts for small-scale Liquefied Natural Gas (ssLNG) on its platform in a bid to address the demand for fuel in areas not connected to the national gas grid.

“The introduction of ssLNG contracts on IGX aims to address the growing gas demand from industries and CGD (City Gas Distribution) companies that do not have access to pipeline networks,” IGX said in a statement.

Through ssLNG, they can now procure liquefied gas through LNG tankers at competitive rates under daily, fortnightly and monthly contracts. Initially, this contract is launched at Dahej and Hazira LNG terminals in Gujarat.

Later, it will be launched at other terminals namely Dhamra in Odisha, Mundra in Gujarat, Ennore in Tamil



Nadu, Kochi in Kerala, and on-land ssLNG stations at Vijaipur.

Natural gas is primarily supplied through pipelines in the country. As a result, industries and commercial establishments without access to the grid primarily rely on trucks for LNG transportation.

The demand for road-transported LNG is projected to increase to 5 million standard cubic metre per day over the next five years.

Small-scale LNG contracts present a win-win situation for both the buyers as well as sellers. It would serve as a platform for sellers, who can

come and trade LNG. Transporting natural gas in liquefied form via trucks will allow larger volumes to be transported, potentially making it economically viable for buyers not connected to pipelines. Further, it will also ensure a transparent and fair procurement process with enhanced payment security.

Speaking at the occasion, PNGRB member Anjani Kumar Tiwari said, “Small-scale LNG serves as the cornerstone for our gas-based economy, enabling us to expand our reach beyond traditional pipelines. On the supply side, it can bring gas from remote and difficult fields and on the demand side, it can help an industry source gas which is not connected to the gas grid.”

“With this vision, we provided approval to IGX for launching ssLNG contracts on their platform. PNGRB endeavours to be a facilitator to support the growth of ssLNG in India by providing a comprehensive regulatory framework,” he said.



एलएनजी अनुबंध की पेशकश

नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) से मंजूरी मिलने के बाद इंडियन गैस एक्सचेंज (आईजीएक्स) ने अपने मंच पर छोटे पैमाने पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एसएसएलएनजी) के लिए अनुबंध जारी किए हैं। इससे राष्ट्रीय गैस ग्रिड से नहीं जुड़े क्षेत्रों में ईंधन की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

आईजीएक्स ने एक बयान में कहा, 'आईजीएक्स पर एसएसएलएनजी अनुबंधों की शुरुआत का उद्देश्य उन उद्योगों और शहरी गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों की तरफ से आ रही बढ़ती गैस मांग को पूरा करना है जिनकी पाइपलाइन नेटवर्क तक पहुंच नहीं है।' (एजेंसी)

आईजीएक्स के मंच पर छोटे पैमाने के एलएनजी अनुबंध की पेशकश

नई दिल्ली, (भाषा)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) से मंजूरी मिलने के बाद इंडियन गैस एक्सचेंज (आईजीएक्स) ने अपने मंच पर छोटे पैमाने पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एसएसएलएनजी) के लिए अनुबंध जारी किए हैं।

इससे राष्ट्रीय गैस ग्रिड से नहीं जुड़े क्षेत्रों में ईंधन की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। आईजीएक्स ने एक बयान में कहा, 'आईजीएक्स पर एसएसएलएनजी अनुबंधों की शुरूआत का उद्देश्य उन उद्योगों और शहरी गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों की तरफ से आ रही बढ़ती गैस मांग को पूरा करना है जिनकी पाइपलाइन नेटवर्क तक पहुंच नहीं है। एसएसएलएनजी के माध्यम से ये कंपनियां अब दैनिक, पाक्षिक और मासिक अनुबंध के तहत प्रतिस्पर्धी दरों पर एलएनजी टैंकरों के माध्यम से तरलीकृत गैस खरीद सकती हैं। शुरूआत में यह अनुबंध गुजरात के

दहेज और हजीरा एलएनजी टर्मिनलों पर शुरू किया गया है। बाद में इसे ओडिशा में धामरा, गुजरात में मुंद्रा, तमिलनाडु में एन्नोर, केरल में कोच्चि और विजयपुर में एसएस-एलएनजी स्टेशनों पर भी शुरू किया जाएगा।

देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मुख्य रूप से पाइपलाइनों के जरिये की जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय गैस ग्रिड तक पहुंच न रखने वाले उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को एलएनजी परिवहन के लिए ट्रकों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगले पांच वर्षों में सड़क-परिवहन एलएनजी की मांग बढ़कर 50 लाख मानक घन मीटर प्रतिदिन हो जाने का अनुमान है। पीएनजीआरबी के सदस्य अंजनी कुमार तिवारी ने अनुबंध की पेशकश पर कहा, 'हमने आईजीएक्स को अपने मंच पर एसएसएलएनजी अनुबंध लाने की मंजूरी दी है। हम वर्तमान नियमों का भी लगातार मूल्यांकन करेंगे।



छोटे पैमाने के एलएनजी अनुबंध की पेशकश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) से मंजूरी मिलने के बाद इंडियन गैस एक्सचेंज (आईजीएक्स) ने अपने मंच पर छोटे पैमाने पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एसएसएलएनजी) के लिए अनुबंध जारी किए हैं। इससे राष्ट्रीय गैस ग्रिड से नहीं जुड़े क्षेत्रों में ईंधन की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। आईजीएक्स ने कहा, 'आईजीएक्स पर एसएसएलएनजी अनुबंधों की शुरुआत का उद्देश्य उन उद्योगों और शहरी गैस वितरण कंपनियों की तरफ से आ रही बढ़ती गैस मांग को पूरा करना है जिनकी पाइपलाइन नेटवर्क तक पहुंच नहीं है।'

भाषा

भारत, यूएई 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर के गैर-तेल व्यापार लक्ष्य को पार करने की राह पर

सवेरा न्यूज/एजेंसी

नई दिल्ली, 24 अप्रैल : सीईपीए परिषद के निदेशक अहमद अलजनेबी ने कहा कि मई 2022 में मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोनों देश 2030 तक गैर-तेल व्यापार में 100 अरब अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को पार करने की राह पर हैं। यूएई-भारत सीईपीए परिषद (यूआईसीसी) को जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मौके पर पेश किया गया था। दोनों देशों ने मई 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को लागू किया था। अलजनेबी ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर के बाद से यूएई-भारत व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने कहा, 1 मई 2022

व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से यूएई-भारत व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़े

को सीईपीए लागू होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार करीब 15 प्रतिशत बढ़ गया है। दोनों देश 2030 तक गैर-तेल व्यापार में 100 अरब अमरीकी डॉलर हासिल करने के लक्ष्य को पार करने की राह पर हैं। अलजनेबी ने जयपुर में व्यापार गोलमेज बैठक में यह बात कही। दवा, रत्न व आभूषण, पर्यटन, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा, मोटर वाहन कल-पुर्जों और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों के राजस्थान स्थित उद्यमों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से यूएई-भारत सीईपीए परिषद (यूआईसीसी) द्वारा आयोजित किया गया।

सौ अरब डालर पर पहुंचेगा भारत-यूएई गैर तेल व्यापार

नई दिल्ली (भाषा)।

सीईपीए परिषद के निदेशक अहमद अलजनेबी ने बुधवार को कहा कि मई 2022 में मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोनों देश 2030 तक गैर-तेल व्यापार में 100 अरब अमेरिकी डालर के लक्ष्य को पार करने की राह पर हैं।

अलजनेबी ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर के बाद से यूएई-भारत व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने कहा, 'एक मई 2022 को सीईपीए लागू होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार करीब 15 प्रतिशत बढ़ गया है। दोनों देश 2030 तक गैर-तेल व्यापार में 100 अरब डालर



हासिल करने के लक्ष्य को पार करने की राह पर हैं।' अलजनेबी ने जयपुर में व्यापार गोलमेज बैठक में यह बात कही। दवा, रल व आभूषण, पर्यटन, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा, मोटर वाहन कल-पुर्जों और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों के राजस्थान स्थित उद्यमों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से यूएई-भारत सीईपीए परिषद (यूआईसीसी) द्वारा आयोजित किया गया। यह भारतीय उद्यमों के लिए यूएई के साथ अपने जुड़ाव का विस्तार करने के लिए नए मार्ग तथा अवसर तलाशने के एक मंच के रूप में काम करता है। यूएई, भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार कुल मिलाकर 85 अरब अमेरिकी डालर हो गया है।